• वर्ष : 05 • अंक : 02 • जुलाई 2026 • हिन्दी मासिक पत्रिका ₹ 40/-

RNI : CHHHIN 2022/86325

स्वतंत्र बोल

www.swatantrabol.com

बुलडोजर से थर्राया नकटी..

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

नैनो उर्वरक तरल

किसान मित्रों के लिए है वरदान

सभी सहकारी समितियों में उर्वरकों का है पर्याप्त भण्डारण

आधी लागत अच्छी पैदावार

थरहा उपचार

5 मिली / 1 लीटर पानी

» **नैनो डीएपी**

बीज रोपाई से पूर्व थरहे को इस घोल में उपचारित करें

रोपाई के 30-35 दिन बाद

पहला छिड़काव

» नैनो डीएपी – **4 मिली/लीटर**
» नैनो यूरिया प्लस – **4 मिली/लीटर**
» नैनो जिंक – **1 मिली/लीटर**

मिलाकर **पत्तियों** पर छिड़काव करें

रोपाई के 55-60 दिन बाद

दूसरा छिड़काव

» नैनो यूरिया प्लस
4 मिली/लीटर

घोल बनाकर **पत्तियों** पर समान रूप से छिड़काव करें

नैनो जिंक (30-35 दिन)
100 मिली / एकड़

नैनो कॉपर (30-35 दिन)
100 मिली / एकड़

ध्यान रखें

- छिड़काव हेतु **125 लीटर पानी प्रति एकड़** आवश्यक है
- **नैनो यूरिया की मात्रा 500 मिली प्रति एकड़** से अधिक न करें
- **छिड़काव सुबह** या **शाम** के समय करें, तेज धूप में न करें

RNI : CHHHIN 2022/86325

स्वतंत्र बोल

www.swatantrabol.com

वर्ष : 05, अंक : 02, जुलाई 2026

प्रेरणास्त्रोत

स्व. जीवन गिरि गोस्वामी

❀❀❀

संपादक

राहुल गिरि गोस्वामी

❀❀❀

कानूनी सलाहकार

आनंद मोहन तिवारी

दिनेश मिश्रा

❀❀❀

प्रचार-प्रसार-विज्ञापन

शेखर सागर

❀❀❀

ले-आउट/डिजाइन

द्वारिका प्रसाद साहू

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक
राहुल गिरि गोस्वामी द्वारा
डी-317 बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने
टैगोर नगर, रायपुर (छ.ग.)
पिन-492001 से प्रकाशित
एवं सागर प्रिंटर्स, पुरानी बस्ती, रायपुर (छ.ग.)
पिन-492001 से मुद्रित।
सम्पादक - राहुल गिरि गोस्वामी

रजिस्टर्ड कार्यालय
डी-317 बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने
टैगोर नगर, रायपुर (छ.ग.)
पिन-492001
Email : Bolswatantra@gmail.com
Phone : 9754374333

(समस्त न्यायालीन प्रकरणों के
निपटारे के लिए न्याय क्षेत्र रायपुर होगा।)

लक्ष्मी राजवाड़े, चौधरी, श्याम बिहारी... 03

पंडवानी को विश्वप्रसिद्ध करने वाली 'तीजन बाई' 06

नकटी में चला बुलडोजर: प्रधानमंत्री... 09

राज्य सरकार के नीतिगत सुधारों व नवाचारों से राजस्व प्रशासन में आया सकारात्मक बदलाव 14

स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता 25

'नीली क्रांति' से समृद्धि की ओर: मछली... 27

विष्णु का सुशासन: सेवा सेतु से सशक्त... 29

पर्यटकों को लेकर जा रही नाव पलटी, 15 की मौत 31

संपादकीय

नकटी से हुई किरकिरी...

राजधानी में एयरपोर्ट से लगे गांव सम्मानपुर नकटी में अवैध कब्जा की तोड़फोड़ कार्यवाही से सरकार की फजीहत हुई है। भरे बरसात में ग्रामीणों का घर जमीदोंज किया गया, तोड़फोड़ कार्यवाही का वीडियो देख लोग आग बबूला हो गए। डैमेज कंट्रोल करने बीजेपी सरकार को अपने मंत्रियो को उतारना पड़ा। दरअसल नकटी में खाली कराये गए जमीन विधायक कॉलोनी बने या कुछ और.. लेकिन मनमाने तरीके से कब्ज़ा हटाए जाने से प्रभावितो के साथ आम लोगो में नाराजगी रही। सरकार और जिला प्रशासन के अधिकारी भले ही लाख कह लें कि कोई गलत नहीं हुआ, सब ठीक किया गया.. पर ऐसा नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने स्पष्ट शब्दों में इस कार्यवाही को गलत बताया। इस कार्यवाही से सरकार की छवि धूमिल हुई है। इसे सुलझाया जा सकता था पर कुछ अधिकारियो की मनमानी से सरकार की चौतरफा किरकिरी हुई है।

– राहुल गिरी गोस्वामी

विधानसभा का मानसून सत्र

लक्ष्मी राजवाड़े, चौधरी, श्याम बिहारी और दयालदास घिरे

छत्तीसगढ़ विधासभा का मानसून हंगामेदार रहा, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से कुल 1033 सवाल लगाए गए थे। पांच दिनों के सत्र में मंत्री अपनों के निशाने पर थे। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, दयालदास बघेल, श्यामबिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी घिरते दिखे तो विपक्षी विद्यायकों के साथ बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के निशाने पर अपने ही मंत्री थे। सत्र में राममंदिर चंदा चोरी, महतारी वंदन योजना में गड़बड़ी, नकली दवाओं, नकटी में तोड़फोड़, उद्योगपति अनिल अग्रवाल पर हुई एफआईआर पर जोरदार हंगामा हुआ, कांग्रेस ने सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जो औंधे मुँह गिर गया।

लक्ष्मी राजवाड़े घिरी

महतारी वंदन योजना में गड़बडी और नाम जोड़ने को लेकर खरसियां विधायक उमेश पटेल ने मंत्री को घेरा। पटेल ने महतारी वंदन योजना से वंचित और अपात्र हितग्राहियों की सूची मांगा, जिस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने उमेश पटेल को डाटा उपलब्ध कराया, लेकिन जब उमेश पटेल ने संबंधित डाटा को लेकर लक्ष्मी राजवाड़े से प्रश्न किए तो वो सवालों में उलझती नजर आई।

लक्ष्मी राजवाड़े ने उमेश पटेल के सवाल पर कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत 55 हजार से ज्यादा लोग फॉर्म भरने के बाद अलग-अलग कारणों से अपात्र मिले हैं, इनका भुगतान जांच के बाद रोका गया है। वहीं 1 लाख 55 हजार 655 लोगों के बारे में राजवाड़े ने बताया कि इनमें से कई लोगों का EKYC नहीं हुआ हैं इस वजह से इनका वर्तमान में भुगतान रोका गया है।

1 लाख महिलाएं हो गई मृत...

उमेश पटेल के सवाल में राजवाड़े ने बताया कि इस योजना में अपात्र लोग 2 फीसदी हैं. जबकि EKYC के बारे में दोबारा कहा कि 55 हजार लोगों का नहीं हुआ है, जिन्हें 30 जुलाई तक का समय दिया गया है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट उमेश पटेल ने दोबारा पूछा कि 55 हजार आपने EKYC बता दिया है तो बाकी बचे 1 लाख लोगों का पैसा क्यों रोका है? इस बार राजवाड़े ने जो जवाब दिया उससे हर कोई चौक गया। राजवाड़े ने कहा कि 1 लाख महिलाएं मृत हैं। इस जवाब से उमेश पटेल भी हैरान हो गए और अध्यक्ष महोदय से कहा कि माननीय मैं इससे सरल तरीके से नहीं पूछ सकता हूं। जो मैं पूछना चाह रहा हूं आप ही उसका जवाब दे दीजिए।

सदन से किया बहिर्गमन

उमेश पटेल को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मंत्री जी आपको जवाब उपलब्ध करा देंगी, आप चिंता ना करें। शायद यहां सवाल और जवाब समझने का फेर है। अध्यक्ष से आग्रह करने के बाद

उमेश पटेल ने आखिरी सवाल पूछा कि महतारी वंदन योजना का पोर्टल फिर कब खुलेगा.इस पर राजवाड़े ने कहा कि आपने किए हुए वादे पूरे नहीं किए हमने जब किया है तो उसे पूरा करेंगे.माननीय विष्णुदेव साय जल्द ही पोर्टल खोलेंगे. इस पर उमेश पटेल ने ऐतराज जताया और कहा कि विभाग आपका है और इसका फैसला मुख्यमंत्री लेंगे. इस जवाब के बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन से बहिर्गमन किया।

सेवा ग्राम पर सदन गर्म: अजय चंद्राकर ने वित्तमंत्री से मांगा जवाब

विधानसभा में नवा रायपुर के सेवाग्राम परियोजना को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सेवाग्राम पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाने को लेकर सवाल उठाते हुए इसे 'एक व्यक्ति विशेष की स्वेच्छाचारिता' का परिणाम बताया। इस टिप्पणी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद सदन का माहौल गरमा गया।

विधानसभा में नवा रायपुर स्थित सेवाग्राम की वित्तीय और भौतिक स्थिति पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि सेवाग्राम बनाने का निर्णय 10 मार्च 2022 को लिया गया था। परियोजना का उद्देश्य महात्मा गांधी के आत्मनिर्भर ग्राम की अवधारणा को साकार करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और कारीगरों को प्रशिक्षण देना है।

मंत्री ने बताया कि परियोजना के लिए वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक कुल 129 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया। मल्टीपरपज डाइनिंग हॉल, सामुदायिक किचन और प्रसाधन कक्ष पर 3.72 करोड़ रुपये तथा अन्य निर्माण कार्यों पर 104.05 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। सरकार के अनुसार सेवाग्राम के सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि इसके संचालन के लिए अभी तक कोई अलग सेटअप स्वीकृत नहीं किया गया है।

मंत्री के जवाब के बाद भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि 'एक व्यक्ति विशेष की स्वेच्छाचारिता की वजह से करीब 200 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए।' इस टिप्पणी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तत्काल खड़े हुए और कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने इस बयान का विरोध करते हुए स्पष्टीकरण देने की कोशिश की। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी

टीका-टिप्पणी शुरू हो गई और सदन में कुछ देर तक जोरदार बहस का माहौल बना रहा। अजय चंद्राकर ने बाद में स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को आहत करना नहीं था, और उन्होंने अपनी टिप्पणी से भूपेश बघेल की भावनाएं आहत होने पर सदन में खेद भी व्यक्त किया।

ब्लैकलिस्टेड दवाइयों पर घिरे स्वास्थ्य मंत्री...

छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुजरात में ब्लैकलिस्टेड दवाइयों की छत्तीसगढ़ में सप्लाई का मुद्दा विपक्ष ने उठाया. नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के साथ भूपेश बघेल की अनुपस्थिति में कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को विषय पर घेरा। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि जो दवाइयां गुजरात मे बैन है. उसे छत्तीसगढ़ में बैन क्यों नहीं की. कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मरीजों को बिना क्वालिटी की दवाई सप्लाई हो रही है. क्या हम प्री टेस्ट नहीं करा रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सीजीएमएससी के नियम पहले से बने हुए हैं. हम प्री टेस्ट नहीं कराते हैं, लेकिन जब दवाई आ जाती है, तब हम अपनी लैब में टेस्ट कराते हैं।

पूर्व सीएम भूपेश बघेल की अनुपस्थिति में विधायक अटल श्रीवास्तव ने पूछा कि क्या यह सत्य है कि दवा निर्माता कंपनी मेसर्स 'यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड' द्वारा प्रदायित एस्पिरिन टैबलेट्स आइपी' गुणवत्ता मानकों पर विफल होने के कारण गुजरात राज्य द्वारा ब्लैकलिस्टेड की गई थी? यदि हाँ, तो क्या इसकी आधिकारिक संसूचना छत्तीसगढ़ शासन या सीजीएमएससी को प्राप्त हुई थी?

इसके साथ विधायक ने पूछा कि क्या यह भी सत्य है कि छत्तीसगढ़ में इसी अमानक औषधि के क्रय एवं आपूर्ति आदेश को त्वरित स्वीकृति प्रदान की गई? यदि हाँ, तो स्थापित वित्तीय नियमों को शिथिल करने हेतु कौन से लोकसेवक उत्तरदायी हैं? इस प्रतिबंधित अवधि के दौरान या उसके बाद उक्त कंपनी से कुल कितनी मात्रा एवं किस संविदा दर पर औषधियां क्रय की गईं? कुल कितना वित्तीय भुगतान किया गया तथा क्या क्रय-पूर्व अनिवार्य बैच-परीक्षण संपन्न कराया गया था? क्रय नियमों के इस गंभीर उल्लंघन पर विभाग द्वारा दोषी अधिकारियों एवं क्रय समिति के विरुद्ध अब तक की गई दंडात्मक कार्रवाई का पूर्ण विवरण क्या है? जवाब में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि यह सत्य है कि गुजरात मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दवा निर्माता कंपनी मेसर्स यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड के औषधि एस्पिरिन टैबलेट्स आइपी (एस्पिरिन गैस्ट्रो-रजिस्टेन्ट टैबलेट्स आइपी 150 मिलीग्राम एवं एस्पिरिन गैस्ट्रो-रजिस्टेन्ट टैबलेट्स आइपी 75 मिलीग्राम) को गुणवत्ता मानकों पर विफल होने के कारण ब्लैकलिस्ट की गई थी. उक्त के संबंध दिनांक 25.03.2026 को फर्म यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड द्वारा सीजीएमएससी लिमिटेड को सूचना प्राप्त हुई थी। इसके साथ मंत्री ने कहा कि यह सत्य नहीं है कि छत्तीसगढ़ में इसी अमानक औषधि के क्रय एवं आपूर्ति आदेश को त्वरित स्वीकृति प्रदान की गई थी. अपितु सत्य तो यह है कि सीजीएमएससी लिमिटेड द्वारा फर्म यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड को औषधि एस्पिरिन टैबलट्स आइपी 75 मिलीग्राम (अनकोटेड टैबलेट) की आपूर्ति हेतु क्रय आदेश जारी किया गया था, जो कि इंडियन फॉर्माकोपिया 2022 अनुसार, गुजरात मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेश लिमिटेड द्वारा प्रतिबंधित किए गए औषधि (एस्पिरिन गैस्ट्रो-रजिस्टेन्ट टैबलेट्स आइपी 150 मिलीग्राम एस्पिरिन गैस्ट्रो-रजिस्टेन्ट टैबलेट्स आइपी 75 मिलीग्राम) से भिन्न है।

पंडवानी को विश्वप्रसिद्ध करने वाली 'तीजन बाई'

तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को भिलाई के गनियारी गांव में हुआ था। वे पारधी समुदाय से थीं। देश-विदेश में पंडवानी लोक गायिकी को पहचान दिलाने वाली तीजन की जिंदगी का सफर आसान नहीं रहा। इसी गायिकी की वजह से उन्हें समाज ने बेदखल कर दिया था। समाज से निकाले जाने के बाद भी उन्होंने गाना नहीं छोड़ा। उनके पिता का नाम चुनुकलाल और माता का नाम सुखवती था। तीजन अपने नाना ब्रजलाल को महाभारत की कहानियां गाते-सुनाते देखतीं थी। धीरे-धीरे उन्हें ये कहानियां याद हो गई। उनकी लगन और प्रतिभा को देखकर गायक उमेद सिंह देशमुख ने उन्हें प्रशिक्षण दिया। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला मंच प्रदर्शन किया। उस समय में महिला पंडवानी गायिकाएं केवल बैठकर गा सकती थीं, जिसे वेदमती शैली कहा जाता है। पुरुष खड़े होकर कापालिक शैली में गाते थे। तीजनबाई वे पहली महिला थीं, जिन्होंने कापालिक शैली में पंडवानी की।

कभी स्कूल नहीं गईं, 4 बार मिली डी. लिट. की उपाधि

बचपन में स्कूल का मुंह न देख पाने वाली पंडवानी गायिका तीजन बाई साक्षरता अभियान में किसी तरह पांचवीं की सीढ़ी ही चढ़ पाईं। लेकिन उनकी पंडवानी की ऐसी धूम रही कि उन्हें भारत के 3 नागरिक सम्मानों से नवाजा गया। तीजन बाई को 4 बार डॉक्टर ऑफ लिटरेचर यानी डी.लिट. की उपाधि मिली।

बेटे ने कहा- मां ने हर किसी का सहयोग किया

अलीम बंसी ने कहा तीजन बाई के बेटे की मौत के बाद उन्होंने मुझे ही अपना बेटा माना। उनका बातों को याद करते हुए अलीम ने कहा कि मां ने कहा था- कभी भी दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर मत चलाना।

27 मई को रायपुर एम्स में कराया गया था भर्ती

परिजनों ने बताया कि रात 3:15 बजे डॉक्टरों ने जानकारी दी कि मां की सांसे थम चुकी है। उन्हें 27 मई को रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया था।

पीएम मोदी ने ली थी स्वास्थ्य की जानकारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने तीजन बाई की बहू वेणु देशमुख को फोन लगाकर उनका हालचाल पूछा था। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने चिंता जताई थी और हरसंभव मदद का आश्वासन दिया था। वेणु ने बताया, प्रधानमंत्री ने तबीयत पर अफसोस जताते हुए कहा था कि उनका ध्यान रखिए। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो सीधे मुझसे संपर्क कीजिए। तीजन बाई जी छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा की धरोहर हैं।

विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम कर रही थी निगरानी

तीजन बाई पिछले करीब 2 सालों से बीमार थीं। कुछ दिनों पहले उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के चलते अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर में भर्ती कराया गया था। एम्स में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी विशेष निगरानी कर रही थी।

छत्तीसगढ़ की लोक कला और पंडवानी गायन को वैश्विक पहचान दिलाने वाली पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन हो गया। वे 70 साल की थीं। उन्होंने शनिवार रात 3.15 बजे रायपुर एम्स में अंतिम सांस ली। वे पिछले कुछ समय से बीमार थीं।

जानकारी के मुताबिक तीजन बाई को सांस लेने में तकलीफ और उम्र से संबंधित अन्य परेशानियां थीं।

तिरंगे में लपेटा गया पार्थिव शरीर

पद्म विभूषण तीजन बाई को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। उनके पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में लपेटा गया है। गनियारी गांव में पूरे धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है।

अंतिम विदाई देने उमड़ा जनसैलाब

तीजन बाई की अंतिम यात्रा में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। अपने प्रिय लोक कलाकार को अंतिम विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा है।

भारतीय लोक कला में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। रविवार सुबह 11 बजे तीजन बाई के शव को उनके पैतृक गांव गनियारी लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं, बल्कि विदेशों तक में नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को सुनाने की प्रेरणा उन्हें नाना से मिली थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के निधन पर शोक जताया। उन्होंने X पर लिखा, 'उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनियाभर में पहचान दिलाई। उनका जाना कला और संस्कृति जगत के लिए अपूरणीय क्षति है।' छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पंडवानी के जरिए उन्होंने देश-विदेश में राज्य का नाम रोशन किया।

फूल अर्पित कर दी श्रद्धांजलि

दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह, एसपी विजय अग्रवाल, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक ललित चंद्राकर, विधायक डोमलाल कोर्सेवाड़ा सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने तीजन बाई के पार्थिव शरीर पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

भूपेश बघेल बोले- एक महान कलाकार आज विदा हो गया

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पद्म विभूषण तीजन बाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने गनियारी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तीजन बाई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए

उनसे जुड़ी पुरानी यादें साझा कीं। भूपेश बघेल ने कहा कि जब वे स्कूल में पढ़ते थे, तब साइकिल से पंडवानी सुनने जाया करते थे। उन्होंने कहा कि तीजन बाई ने अपनी अद्भुत कला से छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को देश-दुनिया में नई पहचान दिलाई।

राज्य सरकार ने लिए कई ऐतिहासिक फैसले

छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति और पंडवानी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने वाली महान लोकगायिका स्वर्गीय डॉ. तीजन बाई की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। रायपुर में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने घोषणा की कि अब हर वर्ष कलाकारों को 'डॉ. तीजन बाई राज्य अलंकरण सम्मान' दिया जाएगा, साथ ही उनके पैतृक गांव गनियारी को 'कलाग्राम' के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा, डॉ. तीजन बाई के ऐतिहासिक तंबूरे को रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में संरक्षित किया जाएगा और सरकार ने उनके परिजनों को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की है।

डॉ. तीजन बाई के नामकरण पर होगी गनियारी के शासकीय हाई-हायर सेकेंडरी स्कूल

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने विश्वविख्यात पंडवानी गायिका, पद्मविभूषण से सम्मानित एवं छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति की अप्रतिम धरोहर डॉ. तीजन बाई के गृहग्राम गनियारी स्थित निवास पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके उपरांत वे उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए तथा दाह संस्कार कार्यक्रम तक उपस्थित रहकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने घोषणा किया कि उनके गृहग्राम गनियारी स्थित शासकीय हाई-हायर सेकेंडरी स्कूल का नामकरण 'डॉ. तीजन बाई शासकीय हाई-हायर सेकेंडरी विद्यालय, गनियारी' के नाम से किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री श्री यादव ने कहा कि डॉ. तीजन बाई ने अपनी अद्वितीय कला-साधना, ओजस्वी वाणी और आजीवन समर्पण के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकसंस्कृति को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई। उनका निधन छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक चेतना के एक स्वर्णिम अध्याय का अवसान है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करने तथा शोकाकुल परिजनों एवं असंख्य प्रशंसकों को इस दु:ख की घड़ी में संबल देने की प्रार्थना की।

मंत्री श्री यादव ने कहा कि डॉ. तीजन बाई का संपूर्ण जीवन लोकपरंपराओं, संस्कृति और कला के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समर्पित रहा। उनकी कला साधना, संघर्ष और उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत बनी रहेंगी। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को विश्व पटल पर स्थापित करने में उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा।

श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने डॉ. तीजन बाई के सम्मान में उनके गृहग्राम गनियारी स्थित शासकीय हाई-हायर सेकेंडरी स्कूल का नामकरण 'डॉ. तीजन बाई शासकीय हाई-हायर सेकेंडरी विद्यालय, गनियारी' के नाम से किया जाएगा। राज्य सरकार का यह निर्णय महान लोककलाकार के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगा तथा इससे भावी पीढ़ियों को उनके प्रेरणादायी व्यक्तित्व, जीवन-संघर्ष और सांस्कृतिक योगदान से निरंतर प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी।

नकटी में चला बुलडोजरः प्रधानमंत्री आवास और पक्के मकान जमीदोज

छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर हवाई अड्डे के पास स्थित इस गांव में 29 जून 2026 की तड़के की सुबह जिला प्रशासन और पुलिस ने बुलडोजर चलाकर 80 से अधिक मकानों को अवैध अतिक्रमण बताते हुए ढहा दिया। जानकारी के अनुसार बस्ती उजाड़कर यहां छत्तीसगढ़ के विधायकों के लिए कॉलोनी बनाने की तैयारी की जा रही है जबकि वे वर्षों से इस जमीन पर रह रहे थे।

छत्तीसगढ़ का नकटी गांव इस समय पूरे छत्तीसगढ़ समेत देश में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में यहां बुलडोजर कार्यवाही की गई जिसमें 80 से अधिक घरों को अवैध अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया। लेकिन गांव के लोग अपने घर और जमीन के अधिकार की लड़ाई पर आज भी डटे हुए हैं। यह घटना एक गांव की कहानी समेत उस सवाल को भी सामने लाती है जो आज देश के कई हिस्सों में उठ रहा है। जैसे अगर देखें तो देश में इस वक्त बुलडोजर चलने की खबर नई नहीं रह गई है। अखबार के किसी न किसी पन्ने पर रोज कहीं न कहीं बुलडोजर कार्रवाई की खबर दिखाई देती है। प्रशासन इन कार्रवाइयों को अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही बताता है। लेकिन अगर हर जगह लोगों के घर अवैध बताए जा रहे हैं तो सवाल है कि जिन लोगों ने वर्षों से वहां रहकर अपनी जिंदगी बसाई सरकारें चुनीं और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाई उनकी जगह और अधिकार (वोट देना) को आखिर किस नजर से देखा जा रहा है।

एक और बात जो बार-बार सामने आती है वह यह है कि बुलडोज़र अक्सर वहीं पहुंचता है जहां मजदूर, गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग रहते हैं चाहे वे उस जगह पर दशकों से क्यों न बसे हों। पहले यह तस्वीर शहरों तक सीमित थी लेकिन अब गांव भी इससे अछूते नहीं रहे हैं।

देश में इस वक्त या तो पेड़ काटे जा रहे हैं या फिर

बुलडोज़र चलाया जा रहा है और ये दोनों बातें कहीं न कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं। पेड़ काटकर या तो कोई माइंस या खदान बनाई जा रही है और बुलडोज़र चलने के बाद उस जमीन को किसी कंपनी को बेच दिया जाता है ताकि वह वहां अपनी जरूरत के मुताबिक कुछ भी कर सके। बुलडोजर की इन कार्रवाइयों के पीछे विकास की बात कही जाती है लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत आम आदमी ही चुकाते रहे हैं

नकटी गांव में तोड़फोड़ की कार्यवाही

नकटी गांव इसका ताजा उदाहरण है। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर हवाई अड्डे के पास स्थित इस गांव में 29 जून 2026 की तड़के की सुबह जिला प्रशासन और पुलिस ने बुलडोजर चलाकर 80 से अधिक मकानों को अवैध अतिक्रमण बताते हुए ढहा दिया। जानकारी के अनुसार बस्ती उजाड़कर यहां छत्तीसगढ़ के विधायकों के लिए कॉलोनी बनाने की तैयारी की जा रही है जबकि वे वर्षों से इस जमीन पर रह रहे थे।

29 जून की सुबह लोगों की नींद बुलडोज़र की आवाज से खुली। कार्रवाई से पहले तड़के करीब 4 बजे पूरे इलाके की बिजली काट दी गई। इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर 80 से अधिक घरों को गिरा दिया। देखते ही देखते कई परिवार बेघर हो गए। जिन घरों में कुछ घंटे पहले तक लोग रह रहे थे वहां सिर्फ मलबा बचा था। उस रात बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं समेत कई

परिवारों को खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ी।

उसी रात करीब 11:30 बजे कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय प्रभावित परिवारों से मिलने गांव पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें अपनी परेशानियां बताईं। कांग्रेस नेता द्वारा ही गांव वालों को बताया गया कि पुनर्वास के नाम पर जो 12 से 14 सदस्यों वाले परिवारों को सिर्फ एक कमरा दिया जा रहा है वहां न बिजली की व्यवस्था है न पानी और न ही शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाए उपलब्ध हैं।

ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार कार्रवाई से दो दिन पहले ही वे रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल से मिले थे। सांसद ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि बरसात के दौरान कोई तोड़फोड़ नहीं होगी और प्रशासन के साथ बातचीत कर कोई समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद बुलडोजर की कार्रवाई रातों-रात हो गई।

बेरही बाई गांव की स्थानीय महिला द्वारा बताया गया कि रात में एक घर तीन से चार बुलडोजर चलवाया गया जिसके कारण मलबे में चार गाय और भैंस दबे मिले। वे सवाल करती हैं कि सरकार का कहना है कि जमीन ग्रामीणों द्वारा कब्जा किया गया है लेकिन अब सरकार बुलडोज़र चला रही है क्या उसे कब्जा नहीं कहा जाएगा? उन्होंने बताया कि वे इस गांव में 30-40 साल से रह रहे हैं।

लोगों से बात करने के दौरान एक दूसरी बात भी सामने आई कि सरकार की ओर से आरोप लगाया गया कि गांव के लोग लाखों रुपये के पक्के घर बनाकर रह रहे है उन्हें गरीब नहीं माना जा सकता। लेकिन गांव की एक महिला की कहानी इस दावे से बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाती है।

महिला ने बताया कि उनके पास तीन एकड़ जमीन थी और उसके अलावा उनकी कोई दूसरी संपत्ति नहीं थी। उन्होंने अपने चारों बेटों के लिए एक घर बनाने के लिए अपनी पूरी जमीन बेच दी। लेकिन बुलडोजर कार्रवाई में वह घर भी टूट गया। अब उनके पास न जमीन बची है और न ही रहने के लिए घर। अपनी यही पीड़ा मीडिया के सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि जिस घर को बनाने के लिए उन्होंने अपनी वर्षों की जमा-पूंजी और जमीन तक बेच दी उसी को सरकार ने यह कहकर तोड़ दिया कि यहां रहने वाले लोग गरीब नहीं हैं और लाखों रुपये के घरों में रहते हैं। महिला का कहना है कि यह जमीन उनकी अपनी थी और वह पिछले 30 वर्षों से अपने बेटों के साथ वहीं रह रही थीं। अब इस कार्रवाई के बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचा है।

गांव में जमीन का विवाद, वैध है या अवैध

सरकारी प्रशासन का तर्क है कि नकटी गांव की करीब 15 हेक्टेयर जमीन शासकीय भूमि है। यह क्षेत्र नवा रायपुर के प्रशासनिक केंद्र के पास स्थित है और यहां नए विधायक आवास बनाए जाने का प्रस्ताव है। हाउसिंग बोर्ड के अनुसार भी यह जमीन उसके अधीन नहीं बल्कि राजस्व विभाग की शासकीय भूमि है जहां विशेष आवासीय परियोजनाएं और विधायक आवास विकसित किए जाने हैं।

प्रशासन और धरसींवा क्षेत्र के विधायक अनुज शर्मा का कई बार कहना रहा है कि किसी भी परिवार को बेघर नहीं होने दिया जाएगा। प्रभावित परिवारों के लिए नवा रायपुर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के फ्लैट आवंटित किए गए हैं। साथ ही हाउसिंग बोर्ड ने पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था देखने के लिए एक समिति भी बनाई है।

वहीं, बेघर हुए ग्रामीणों का दावा है कि वे पिछले 50 - 60 वर्षों से यहां रह रहे हैं और वो जमीन उनकी निजी या पुश्तैनी जमीन है। हालांकि मामला यहीं खत्म नहीं होता। प्रशासन का कहना है कि नकटी गांव के 80 घर अवैध रूप से बसे हुए थे।

राम मंदिर चंदा चोरी से आहत्

अयोध्या का राम मंदिर केवल पत्थरों, स्तंभों और शिल्प का विराट स्थापत्य नहीं है; वह करोड़ों हिंदुओं की आस्था, भावनाओं और सांस्कृतिक चेतना का जीवंत केंद्र है। इस मंदिर से जुड़ी हर ईंट, हर दानराशि और हर व्यवस्था केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, बल्कि उस विश्वास का प्रतीक है, जिसे देश-विदेश के रामभक्तों ने अपनी श्रद्धा से सींचा है। ऐसे में यदि मंदिर के चंदे, दानराशि या उससे जुड़े आर्थिक प्रबंधन पर अनियमितता, गबन, चोरी या दुरुपयोग जैसे आरोप सामने आते हैं, तो यह केवल वित्तीय गड़बड़ी का मामला नहीं रह जाता; यह सीधे-सीधे आस्था पर प्रहार का प्रश्न बन जाता है। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा/धन अनियमितता विवाद ने इसी कारण सामान्य प्रशासनिक प्रकरण की सीमा पार कर व्यापक सामाजिक, धार्मिक और नैतिक चिंता का रूप ले लिया है।

इस पूरे विवाद में जो बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वह यह कि अब इसे अफवाह, राजनीतिक बयानबाजी या संगठनात्मक बचाव की परतों में दबाने के बजाय स्पष्ट, त्वरित और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया के हवाले किया जाना चाहिए। यदि विशेष जांच दल की प्रारंभिक रिपोर्ट में कुछ नाम सामने आए हैं और प्रथम दृष्टया अनियमितता की पुष्टि के संकेत मिले हैं, तो अगला स्वाभाविक कदम तत्काल प्राथमिकी दर्ज करना होना चाहिए। कानून का पहला दायित्व यही है कि वह किसी भी आरोप को या तो प्रमाणित करे या झूठा सिद्ध करे; किंतु यह कार्य तभी संभव है जब जांच में गति, गंभीरता और स्वतंत्रता हो। वर्षों तक फाइलें पलटते रहने, जांच को ठंडे बस्ते में डालने या समय के साथ जनाक्रोश के शांत हो जाने की प्रतीक्षा करना इस मामले में सबसे बड़ी भूल होगी। जिस धन को करोड़ों श्रद्धालुओं ने 'रामजी का धन' मानकर समर्पित किया हो, उसके संबंध में न्यायिक प्रक्रिया जितनी तेज और पारदर्शी होगी, उतना ही समाज का विश्वास बचा रहेगा। यही कारण है कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में हो और कुछ महीनों के भीतर दोषियों की जवाबदेही तय हो—यह मांग न केवल उचित है, बल्कि आवश्यक भी है।

इस विवाद का दूसरा और अधिक संवेदनशील पक्ष यह है कि इसमें किसी भी व्यक्ति के पद, प्रतिष्ठा, संगठनात्मक महत्व या राजनीतिक उपयोगिता के आधार पर रियायत नहीं दी जा सकती। राम मंदिर जैसा संस्थान किसी व्यक्ति विशेष की निजी जागीर नहीं है; वह समस्त हिंदू समाज की सामूहिक आस्था का केंद्र है। इसलिए यदि कोई छोटा कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसे दंड मिले, और यदि किसी बड़े पदाधिकारी,

प्रभावशाली प्रबंधक या प्रतिष्ठित नाम पर भी आरोप हैं, तो उनकी भी उतनी ही कठोरता से जांच हो। न्याय का अर्थ केवल अपराधी को सजा देना नहीं, बल्कि यह विश्वास स्थापित करना भी है कि कानून के सामने सभी समान हैं। यदि समाज को यह संदेश गया कि छोटे लोगों को बलि का बकरा बनाया गया और बड़े नामों को बचा लिया गया, तो इससे मंदिर प्रशासन ही नहीं, व्यापक धार्मिक नेतृत्व की नैतिक विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लग जाएगा।

इसी संदर्भ में यह भी ध्यान देने योग्य है कि किसी व्यक्ति के प्रति निजी सम्मान और उसके विरुद्ध लगे आरोपों की जांच—ये दो अलग-अलग बातें हैं। किसी पदाधिकारी की पूर्व प्रतिष्ठा, लंबे सार्वजनिक जीवन या व्यक्तिगत छवि के आधार पर जांच से छूट नहीं दी जा सकती। यदि आरोप असत्य हैं, तो निष्पक्ष जांच उसे भी सिद्ध कर देगी; और यदि आरोपों में दम है, तो फिर सम्मान, निकटता या संगठनात्मक संबंध किसी को संरक्षण नहीं दे सकते। धार्मिक संस्थाओं की सबसे बड़ी शक्ति उनके अनुयायियों का विश्वास है, और यह विश्वास केवल निष्ठा से नहीं, बल्कि जवाबदेही से भी अर्जित होता है।

लेकिन इस पूरे प्रकरण की सबसे बड़ी सीख केवल दोषियों की खोज में नहीं, बल्कि व्यवस्था की खामियों को समझने में छिपी है। प्रश्न यह है कि क्या इतने विशाल और संवेदनशील धार्मिक संस्थान का प्रशासन आज भी केवल व्यक्तिगत भरोसे, परंपरागत शैली या अनौपचारिक व्यवस्था के सहारे चल सकता है? उत्तर स्पष्ट रूप से 'नहीं' है। जब करोड़ों की दानराशि, देशव्यापी श्रद्धा और विशाल संस्थागत ढांचा दांव पर हो, तब प्रशासनिक ढिलाई स्वयं में जोखिम बन जाती है। मंदिरों और धार्मिक ट्रस्टों को अब यह स्वीकार करना होगा कि श्रद्धा और आधुनिक प्रबंधन एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। जिस प्रकार किसी बड़े सार्वजनिक संस्थान में वित्तीय अनुशासन, बहुस्तरीय लेखा-परीक्षा, डिजिटल रिकॉर्ड, स्वतंत्र ऑडिट, जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन और नियमित निगरानी अनिवार्य होती है, उसी प्रकार बड़े धार्मिक ट्रस्टों में भी कठोर मानक संचालन प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। दान की प्राप्ति से लेकर उसके उपयोग तक हर स्तर पर लिखित प्रक्रिया, सत्यापन तंत्र और जवाबदेही की श्रृंखला होनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति के विवेक, प्रभाव या ईमानदारी पर पूरी व्यवस्था टिकी रहे—यह मॉडल अब न पर्याप्त है, न सुरक्षित।

यह भी उतना ही सच है कि ऐसे मामलों में राजनीतिक दल अवसर खोजते हैं। चांदी की ईंटों, रसीदों या अन्य आरोपों को लेकर जो सार्वजनिक शोर उठता है, उसमें तथ्य और प्रचार अक्सर एक-दूसरे में घुलमिल जाते हैं। इसलिए किसी भी दावे को केवल इसलिए सत्य मान लेना कि वह सनसनीखेज है, या केवल इसलिए झूठा मान लेना कि वह विरोधियों की ओर से आया है—दोनों ही अतिवादी स्थितियाँ हैं। सही मार्ग यही है कि राजनीतिक शोर से परे जाकर पुलिस, जांच एजेंसियां और न्यायालय तथ्य के आधार पर निष्कर्ष दें। परंतु यह निष्कर्ष तभी विश्वसनीय होगा, जब जांच न केवल निष्पक्ष हो, बल्कि निष्पक्ष दिखाई भी दे।

अंतत:, राम मंदिर का प्रश्न केवल एक मंदिर का प्रश्न नहीं है; यह उस नैतिक कसौटी का प्रश्न है जिस पर हिंदू समाज अपने सबसे बड़े प्रतीकों को परखता है। यदि आस्था के केंद्रों में पारदर्शिता, अनुशासन और उत्तरदायित्व नहीं होगा, तो विरोधियों के आरोपों से अधिक नुकसान भीतर की शिथिलता करेगी। इसलिए इस प्रकरण का सबसे उचित समाधान यही है कि दोषियों को शीघ्र और कठोर दंड मिले, निर्दोषों को स्पष्ट रूप से न्याय मिले, और मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था को ऐसी पारदर्शी, आधुनिक और उत्तरदायी प्रणाली में बदला जाए, जिस पर भक्तों का विश्वास पहले से अधिक दृढ़ होकर लौटे। राम मंदिर केवल श्रद्धा का प्रतीक नहीं, बल्कि मर्यादा का भी प्रतीक है; और मर्यादा का पहला नियम यही है कि 'रामजी के धन' पर किसी भी प्रकार का अंधेरा सहन नहीं किया जा सकता।

– कैलाश चन्द्र

राज्य सरकार के नीतिगत सुधारों व नवाचारों से राजस्व प्रशासन में आया सकारात्मक बदलाव

राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता, तकनीक आधारित समाधान व समयबद्ध निराकरण के निर्देश

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। उन्होंने विभाग द्वारा किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों, तकनीक आधारित नवाचारों तथा नागरिकों एवं किसानों को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों की समीक्षा करते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार की स्पष्ट नीति राजस्व प्रशासन को पारदर्शी, जवाबदेह एवं भ्रष्टाचारमुक्त बनाना है। राजस्व मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी तथा नागरिकों को बिना अनावश्यक कार्यालयीन आवागमन के गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

बैठक में डिजिटल किसान किताब एवं भूमि संबंधी दस्तावेजों के डिजिटलीकरण की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसानों को बी-1, खसरा, ऋण पुस्तिका तथा भूमि संबंधी अन्य जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से सहज रूप से उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि उन्हें तहसील अथवा पटवारी कार्यालय जाने की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग सीधे आमजन एवं किसानों के जीवन से जुड़ा विभाग है, इसलिए शासन के सभी सुधारों एवं नवाचारों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध रूप से पहुंचना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने आरबीसी 6-4 के प्रकरणों का त्वरित एवं संवेदनशीलता के साथ निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आरबीसी 6-4 की ऑनलाइन व्यवस्था एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिसके लागू होने पर आवेदक स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे तथा संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध होगी। उन्होंने अविवादित फौती नामांतरण की प्रक्रिया

पंचायतों के माध्यम से संपादित करने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर विशेष बल देते हुए सीमांकन प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निपटारा सुनिश्चित करने तथा समय-सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों की जिला-वार नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।

बैठक में VASUNDHARA (Verified Accessible System for Unified Digital Land Records & Historical Archives) परियोजना की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने नकल शाखा को पूर्णतः ऑनलाइन करने के लिए इस परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिला एवं तहसील कार्यालयों के महत्वपूर्ण राजस्व अभिलेखों का एकीकृत डिजिटल अभिलेखागार विकसित किया जाएगा। इससे प्रमाणित अभिलेखों का निर्गमन कुछ ही मिनटों में संभव होगा तथा अभिलेखों में छेड़छाड़ की संभावनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने असर्वेक्षित ग्रामों, विशेषकर अबूझमाड़ क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए

निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि राजस्व अभिलेख तैयार हो सकें, भूमि अभिलेख अद्यतन हों तथा स्थानीय नागरिकों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

बैठक में स्वामित्व योजना, वन अधिकार पट्टों की प्रविष्टि एवं नामांतरण, पट्टाधृति अधिनियम-2023 के प्रभावी क्रियान्वयन, एग्री स्टैक, फार्मर रजिस्ट्री एवं एक्सेम्प्टेड कैटेगरी फार्मर रजिस्ट्री की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने आगामी खरीफ सीजन के डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं गिरदावरी की सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन का उद्देश्य केवल प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण नहीं, बल्कि नागरिकों को तेज, पारदर्शी, जवाबदेह एवं विश्वासपूर्ण राजस्व व्यवस्था उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के नीतिगत सुधारों एवं नवाचारों से राजस्व प्रशासन में सकारात्मक परिवर्तन आया है और इसे और अधिक प्रभावी बनाना सभी अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

बैठक में साइबर तहसील व्यवस्था लागू करने की संभावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस व्यवस्था के माध्यम से अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा सहित विभिन्न राजस्व सेवाएं केंद्रीकृत एवं पूर्णतः ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा सकेंगी। मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों के अनुभवों का अध्ययन कर नागरिक हित में आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने के निर्देश दिए।

बैठक में ई-कोर्ट प्रणाली, रेवेन्यू बोर्ड एवं संभागीय आयुक्त कार्यालयों में ऑनलाइन साक्ष्य प्रस्तुत करने की व्यवस्था, नक्शा डिजिटाइजेशन, ऑटो म्यूटेशन, ऑटो डायवर्सन तथा भू-अर्जन से संबंधित विषयों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि धमतरी, अंबिकापुर एवं जगदलपुर में नक्शा परियोजना का पायलट कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसे दिसंबर 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में पटवारी, राजस्व निरीक्षक, लिपिक एवं अन्य रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती, तहसीलों के अधोसंरचना विकास तथा तहसीलदारों के लिए आवश्यक वाहन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।

बैठक में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव प्रभात मलिक, राजस्व विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, विशेष सचिव इफ़्फ़त आरा, संचालक भू-अभिलेख विनीत नंदनवार, संयुक्त सचिव अरविन्द एक्का सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

103 करोड़ रुपये से अधिक के स्वास्थ्य अधोसंरचना कार्यों का भूमिपूजन

स्वस्थ छत्तीसगढ़ करेगा विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह, चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में 103 करोड़ रुपये से अधिक लागत के स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास कार्यों का भूमिपूजन किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ छत्तीसगढ़ ही विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेगा। प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। यह परियोजनाएं प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई प्रदान करेंगी तथा मरीजों, विद्यार्थियों और चिकित्सकों सभी को इसका लाभ मिलेगा।

इस अवसर पर छात्र-छात्राओं के लिए आधुनिक छात्रावास, कैंसर भवन के विस्तार तथा चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के आवासीय परिसर सहित विभिन्न निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पिछली बार मेडिकल कॉलेज आने पर विद्यार्थियों ने छात्रावास निर्माण की मांग रखी थी, जिसे सरकार ने गंभीरता से लेते हुए आज उसके निर्माण की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में जनता से किए गए अधिकांश वादों को पूरा किया है और 'मोदी की गारंटी' को धरातल पर उतारा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और विकसित भारत के संकल्प की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए स्वस्थ छत्तीसगढ़ आवश्यक है। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग लगातार उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों एवं पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार का छत्तीसगढ़ को निरंतर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि डीएम कार्डियक कोर्स की स्वीकृति से लेकर अन्य स्वास्थ्य परियोजनाओं तक केंद्र सरकार ने हर मांग पर सकारात्मक सहयोग दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में छत्तीसगढ़ को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद) की भी सौगात मिलेगी, जिससे राज्य की समृद्ध औषधीय वनस्पतियों एवं आयुर्वेद को नई पहचान मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अब नक्सलवाद से मुक्त होकर तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने दूरस्थ क्षेत्रों में घर-घर पहुंचकर लाखों लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार किया है। उन्होंने मेडिकल विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सरगुजा से लेकर बस्तर तक प्रदेश के हर क्षेत्र में सेवाएं देने का संकल्प लें और केवल शहरों तक सीमित रहने की मानसिकता न रखें।

उन्होंने कहा कि सरकार चिकित्सा शिक्षा के लिए

आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है तथा विद्यार्थियों को बेहतर अधोसंरचना, छात्रावास एवं आधुनिक शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि लगभग 104 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले छात्रावास, कैंसर संस्थान विस्तार एवं अन्य अधोसंरचना परियोजनाएं चिकित्सा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं निर्माण एजेंसियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा से पहले एवं उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं।

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है। राज्य में पांच नए मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति, नर्सिंग कॉलेजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि, फिजियोथेरेपी कॉलेजों का विस्तार तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 10 एकड़ क्षेत्र में 100 बिस्तरों वाले योग एवं नेचुरोपैथी अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर का निर्माण भी प्रगति पर है। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व में लंबित कोरबा, कांकेर एवं महासमुंद मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्य प्रारंभ कराए हैं। बिलासपुर स्थित सिम्स का भी व्यापक उन्नयन किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि डीएम कार्डियक कोर्स प्रारंभ हो चुका है तथा जगदलपुर में जल्द ही छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा हार्ट सेंटर स्थापित किया जाएगा।

कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रथम परियोजना के तहत 200 सीटर आधुनिक छात्र-छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों के लिए आधुनिक आवासीय सुविधाओं के साथ चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के लिए भी आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।

दूसरी परियोजना के तहत कैंसर भवन का द्वितीय से छठे तल तक विस्तार किया जाएगा। लगभग 11 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में बनने वाले इस भवन में आधुनिक लैब, 64-64 बिस्तरों वाले वार्ड, सिंगल रूम, आईसीयू तथा अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर विकसित किए जाएंगे, जिससे कैंसर रोगियों को उच्च स्तरीय उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तीसरी परियोजना के अंतर्गत छात्राओं के लिए आधुनिक छात्रावास का विस्तार किया जाएगा, जिसमें अतिरिक्त कमरे, डॉरमेट्री, लाइब्रेरी, रिक्रिएशन हॉल तथा सभी आवश्यक आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, ताकि छात्राओं को सुरक्षित एवं बेहतर आवासीय वातावरण उपलब्ध हो सके।

इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा, सीजीएमएससी के चेयरमैन दीपक म्हस्के, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा रितेश अग्रवाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के डीन डॉ. विवेक चौधरी, अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर सहित जनप्रतिनिधि, चिकित्सक, मेडिकल विद्यार्थी एवं बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे।

विधायक भावना की पाठशाला..

पंडरिया विधानसभा के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, ड्रोन, 3डी प्रिंटिंग और कोडिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों की शिक्षा उनके स्कूलों तक पहुंचकर दी जाएगी। इस दिशा में विधायक भावना बोहरा की पहल 'भावना दीदी की साइंस पाठशाला' के तहत शुरू की गई मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब का शुभारंभ विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया।

गांव-गांव पहुंचेगी हाईटेक मोबाइल लैब

यह अत्याधुनिक मोबाइल लैब पंडरिया विधानसभा के ग्रामीण, वनांचल और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित शासकीय विद्यालयों के साथ-साथ सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालयों तक पहुंचेगी। इसका उद्देश्य उन विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराना है, जिन्हें अब तक ऐसी सुविधाओं तक आसानी से पहुंच नहीं मिल पाती थी।

एआई, ड्रोन और 3डी प्रिंटिंग का मिलेगा व्यावहारिक प्रशिक्षण

मोबाइल लैब के साथ पांच प्रशिक्षकों की विशेष टीम प्रत्येक विद्यालय में तीन से पांच दिनों तक कार्यशाला आयोजित करेगी। इस दौरान विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, ड्रोन संचालन, एयरोमॉडलिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), ऑगमेंटेड रियलिटी (AR), वर्चुअल रियलिटी (VR), 3डी प्रिंटिंग और कोडिंग जैसी उभरती तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रतिभागी विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए जाएंगे।

एक वर्ष में 5 हजार विद्यार्थियों तक पहुंचने का लक्ष्य

इस पहल का लक्ष्य एक वर्ष के भीतर करीब 5,000 विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी शिक्षा से जोड़ना है। इसके माध्यम से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को भविष्य की तकनीकों, नवाचार और रोजगार के नए अवसरों से परिचित कराने का प्रयास किया जाएगा।

भविष्य की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा जरूरी

शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि नई शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित ज्ञान देना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को भविष्य की जरूरतों और बदलती तकनीकों के अनुरूप

मार्गदर्शन मिले तो वे भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसी सोच के साथ 'भावना दीदी की साइंस पाठशाला' की शुरुआत की गई है, ताकि गांव के बच्चों को भी नई तकनीकों से जोड़कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।

पहले से चल रही हैं कई शैक्षणिक पहल

भावना बोहरा ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में उनकी ओर से पहले से कई पहलें संचालित की जा रही हैं। पंडरिया विधानसभा में संचालित 10 नि:शुल्क बस सेवाओं के माध्यम से 1,500 से अधिक छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए आवागमन की सुविधा मिल रही है। वहीं 'लक्ष्य' नि:शुल्क कोचिंग के जरिए लगभग 250 विद्यार्थियों को IIT-JEE, NEET और CGPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है।

उन्होंने विश्वास जताया कि मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब के माध्यम से क्षेत्र के हजारों विद्यार्थी आधुनिक तकनीकों से जुड़ेंगे और भविष्य में विज्ञान, तकनीक एवं नवाचार के क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त कर सकेंगे।

तैयार करना भी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहलें ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

ग्रामीण प्रतिभाओं को मिलेगा नया मंच

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता केवल उचित अवसर और संसाधन उपलब्ध कराने की है। उन्होंने कहा कि मोबाइल टेक्नोलॉजी लैब के माध्यम से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकों को सीखने और समझने का अवसर मिलेगा, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकेंगे।

संसाधन मिलेंगे तो बच्चे भी करेंगे बेहतर प्रदर्शन

विधायक भावना बोहरा ने कहा कि ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यदि उन्हें आधुनिक संसाधन, तकनीकी शिक्षा और सही

हरी खाद से कम होगी लागत और बढ़ेगी पैदावार

बढ़ती खेती लागत और घटती मिट्टी की उर्वरता के बीच हरी खाद किसानों के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आई है। कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, रायगढ़ के वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि किसान रासायनिक उर्वरकों पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय हरी खाद और हरी पत्तियों की खाद को अपनाएं तो न केवल मिट्टी की सेहत सुधरेगी, बल्कि खेती भी अधिक लाभकारी बनेगी।

वैज्ञानिकों के अनुसार ढैंचा, सनई, मूंग, उड़द, लोबिया और ग्वार जैसी दलहनी फसलें 35 से 45 दिन बाद खेत में मिलाने से प्राकृतिक जैविक खाद में बदल जाती हैं। इससे प्रति हेक्टेयर 50 से 60 किलोग्राम तक नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। वहीं नीम, करंज, ग्लिरिसिडिया और सहजन की हरी पत्तियां भी मिट्टी में जैविक तत्व और लाभकारी सूक्ष्मजीवों की सक्रियता बढ़ाती हैं।

इस प्राकृतिक तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि रासायनिक उर्वरकों की जरूरत घटने से खेती की लागत कम होती है, जबकि फसलों की उपज में 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी देखी गई है। धान की गुणवत्ता में भी सुधार और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ने के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। वैज्ञानिकों ने किसानों से हरी खाद और ब्राउन मैन्योरिंग जैसी तकनीकों को अपनाकर मिट्टी की सेहत बचाने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और टिकाऊ कृषि की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है।

देशभर में धीमी पड़ी मानसून की रफ्तार, बारिश में आई 18 फीसदी कमी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को देश के कई हिस्सों में व्यापक बारिश का पूर्वानुमान जताया है। उत्तर, पूर्व, मध्य और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। कई क्षेत्रों में आंधी और बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है, जबकि राजस्थान में आने वाले दिनों में मानसून कमजोर रहने और ज्यादातर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।

पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में बिजली और तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान आने की उम्मीद है। गांगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज हवाओं के साथ आंधी आ सकती है।

दिल्ली-एनसीआर का मौसम

दिल्ली-एनसीआर में आने वाले दिनों में छिटपुट बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। हालांकि, सोमवार के लिए भारी बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं।

उत्तर भारत का मौसम पूर्वानुमान

हिमालयी राज्यों में मानसून सक्रिय रहने की उम्मीद है, जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी सोमवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरे सप्ताह छिटपुट बारिश होने की उम्मीद है।

राजस्थान में आने वाले सप्ताह में मानसून कमजोर रहने की संभावना है, जिससे राज्य के अधिकांश हिस्से काफी हद तक शुष्क रहेंगे। ढ्ढरूष्ठ ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन अगले कई दिनों तक बारिश की गतिविधि सामान्य से कम रहने की उम्मीद है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।

पूर्वी भारत का मौसम पूर्वानुमान

बिहार में भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी व्यापक बारिश के साथ कुछ इलाकों में तेज बौछारें पड़ने की उम्मीद है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है, जबकि इस सप्ताह के अंत में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश का अनुमान है।

पूर्वोत्तर भारत का मौसम पूर्वानुमान

IMD ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में व्यापक बारिश का अनुमान जताया है। क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की उम्मीद है और यह गतिविधि अगले कई दिनों तक जारी रहने की संभावना है।

मध्य और पश्चिम भारत का मौसम पूर्वानुमान

छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों में बिजली और तेज हवाओं के साथ आंधी आ सकती है। कोंकण और गोवा में व्यापक बारिश जारी रहने की उम्मीद है, जबकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में छिटपुट बारिश होने की संभावना है।

दक्षिण भारत का मौसम पूर्वानुमान

तटीय कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और लक्षद्वीप में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर-पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में अगले तीन से चार दिनों तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी तट तथा मध्य और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भी बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है। IMD ने भारी बारिश की चेतावनी वाले क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि संवेदनशील इलाकों में जलभराव, स्थानीय स्तर पर बाढ़ और यातायात बाधित होने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

देश में 18% पहुंचा बारिश का घाटा

भारत में एक सप्ताह की अच्छी बारिश के बाद मानसून की रफ्तार एक बार फिर धीमी पड़ गई है, जिससे जून के अंत में देशव्यापी बारिश की कमी जो 40% से घटकर 9 जुलाई तक 14% रह गई थी, वह इस सूखे दौर के कारण रविवार तक बढ़कर 18% हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले छह-सात दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम और पश्चिम-मध्य भारत के मैदानी इलाकों के साथ-साथ दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में भी कमजोर बारिश का अनुमान जताया है, जिससे अगले सप्ताह यह घाटा और बढ़ सकता है।

इस सूखे स्पेल से पिछले सप्ताह बुआई गतिविधियों में हुए सुधार को झटका लग सकता है, क्योंकि देश के मुख्य मानसूनी कृषि क्षेत्रों में सिंचाई के सीमित साधनों के कारण खेती मौसमी बारिश पर निर्भर है, जहां वर्तमान में बारिश की भारी कमी देखी जा रही है। यही वजह है कि पिछले साल की समान अवधि की तुलना में इस बार सभी मुख्य फसलों का बुआई क्षेत्र कम दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, इस सप्ताह कुछ बारिश का अनुमान जरूर है, लेकिन यह मानसून के इस बड़े घाटे को पाटने के लिए नाकाफी होगी।

स्थिति यह है कि रविवार तक बिहार, झारखंड, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित 15 राज्यों में संचयी (1 जून से 12 जुलाई) मानसूनी बारिश में 20% से लेकर 73% तक की भारी कमी दर्ज की गई है, जबकि क्षेत्रवार देखा जाए तो बिहार, झारखंड और पांच पूर्वोत्तर राज्यों में कमजोर मानसूनी गतिविधियों के चलते पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज़्यादा 37% का बड़ा घाटा देखा गया है।

‘दिलचस्पी खत्म हो गई होगी’

क्यों टूटी गोविंदा-करिश्मा कपूर की हिट जोड़ी?

शगुफ्ता अली बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. वह कई फिल्मों में अपने हुनर का जलवा बिखेर चुकी हैं. अब उन्होंने साल 1997 की सुपरहिट कॉमेडी फिल्म ‘हीरो नंबर 1’ में करिश्मा कपूर के साथ काम करने के अपने अनुभवों पर खुलकर बात की है. शगुफ्ता ने जहां एक तरफ करिश्मा की कड़ी मेहनत की तारीफ की, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि एक्ट्रेस सेट पर काफी एटीट्यूड दिखाती थीं. शगुफ्ता ने इस पर भी बात की कि बड़े पर्दे पर गोविंदा-करिश्मा की जोड़ी क्यों टूटी.

यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू में जब शगुफ्ता से पूछा गया कि कई सुपरहिट फिल्में देने के बाद भी गोविंदा और करिश्मा कपूर की पॉपुलर जोड़ी आखिर क्यों टूट गई? इस पर शगुफ्ता ने कहा, ‘शायद एक-दूसरे में दिलचस्पी खत्म हो गई होगी, प्यार-मोहब्बत खत्म हो गया होगा. हीरोइनों के मूड का भी क्या भरोसा और बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होना भी अच्छा नहीं होता. करिश्मा ओवर-एंबिशियस थीं. वह मेहनत बहुत करती थीं, लेकिन उनमें एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा था.’

हिट रही करिश्मा कपूर-गोविंदा की जोड़ी

90 के दशक में गोविंदा और करिश्मा कपूर हिंदी सिनेमा की सबसे सफल जोड़ियों में से एक थे. दोनों ने ‘कुली नंबर 1’, ‘राजा बाबू’, ‘साजन चले ससुराल’, ‘हसीना मान जाएगी’ और ‘शिकारी’ जैसी कई यादगार फिल्मों में साथ काम किया है.

आपसी तालमेल होना बेहद जरूरी

शगुफ्ता ने आगे बताया कि क्यों किसी एक्टर-एक्ट्रेस का कैमरे के पीछे का व्यवहार पर्दे पर दिखने वाले काम को प्रभावित करता है, उन्होंने कहा, ‘यह बात हर जगह साफ दिखाई देती थी. आप सेट पर कैसा रवैया रखते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है. अगर कोई आपका को-एक्टर है, तो वहां आपसी तालमेल होना बेहद जरूरी है.

दोनों एक्टर्स को मिलनी चाहिए बराबर जगह

शगुफ्ता का मानना है कि चाहे कोई सीन शूट हो रहा हो या इंटरव्यू, दोनों कलाकारों को एक-दूसरे को बराबर जगह देनी चाहिए उन्होंने आगे कहा, ‘अगर मैं आपको सीन में क्यूज देने के लिए सेट पर मौजूद रहती हूं, तो आपको भी मेरे लिए रुकना चाहिए. और अगर आप नहीं भी रहते, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बिना क्यूज के भी एक्टिंग कर सकती हूं. इसी बदौलत मैं पिछले 40 सालों से इस इंडस्ट्री में टिकी हुई हूं.’

सुपरहिट साबित हुई थी ‘हीरो नंबर 1’ फिल्म

बताते चलें कि डेविड धवन के निर्देशन में बनी फिल्म ‘हीरो नंबर 1’ में शगुफ्ता अली और करिश्मा कपूर ने साथ काम किया था. गोविंदा, कादर खान, परेश रावल और सतीश शाह जैसे सितारों से सजी यह कॉमेडी फिल्म उस दौर की सुपरहिट साबित हुई थी, जिसे आज भी दर्शक बेहद पसंद करते हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो करिश्मा कपूर हाल ही में साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज ‘ब्राउन’ में एक जासूस के दमदार किरदार में नजर आई थीं और आप इसे जी5 पर देख सकते हैं।

'वेलकम टू द जंगल' सबसे बड़ी मल्टीस्टारर फिल्मों में शामिल

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में 34 स्टार्स है। इस बात का खुलासा फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने किया था। उन्होंने यह भी बताया था कि सेट पर करीब 900 लोगों की टीम भी रहती थी। इन सभी चीजों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म का बजट काफी बड़ा था। वहीं, कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आए थे, जिनमें दावा किया जा रहा है कि 'वेलकम टू द जंगल' का बजट करीब 250 से 300 करोड़ रुपए है।

'34 स्टार्स, 900 लोगों की टीम'

किसी हालिया इंटरव्यू में डायरेक्टर ने कहा था– कई दिनों तक सेट पर एक साथ करीब 30 एक्टर्स मौजूद रहते थे। हर एक्टर के साथ करीब 5 लोगों की टीम होती थी। इसके अलावा करीब 200 लोगों का प्रोडक्शन स्टाफ भी मौजूद रहता था। जब स्टंट टीम, एक्शन फाइटर्स, घुड़सवार, 150 से 200 जूनियर आर्टिस्ट और डांसर्स शामिल होते थे, तब सेट पर कुल 700 से 900 लोग काम करते थे। शूटिंग के दौरान रोज करीब 200 से 250 गाड़ियां और 50 वैनिटी वैन सेट पर पहुंचती थीं। इस वजह से दो बड़े मैदान में पूरा सेट तैयार किया गया था।

बॉलीवुड में कई मल्टीस्टारर फिल्में शामिल

'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, आफताब शिवदासानी, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, बोमन ईरानी, रवीना टंडन, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नांडिस, दिशा पाटनी, वामिका गब्बी, आयशा खान, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, जाकिर हुसैन, रंजीत, दलेर मेहंदी, मीका सिंह, राकेश बेदी, सुदेश बेरी और फरीदा जलाल जैसे एक्टर्स नजर आए।

इंडस्ट्री में कई ऐसी फिल्में हैं, जिनकी स्टार कास्ट काफी बड़ी है। इन फिल्मों में शामिल है–

शोले (1975): 'शोले' हिंदी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक मल्टीस्टारर फिल्मों में शामिल है। इसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, अमजद खान, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, जया भादुड़ी, असरानी, जगदीप, ए.के. हंगल और मैकमोहन जैसे कई एक्टर्स थे। उस दौर में फिल्म को काफी पसंद किया गया था। इसने सभी एक्टर्स को एक अलग पहचान दिलवाई थी।

कभी खुशी कभी गम (2001): कभी खुशी कभी गम में करीब लगभग 25 से 30 एक्टर्स थे। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, रानी मुखर्जी और फरीदा जलाल जैसे कई बड़े स्टार्स नजर आए थे।

LOC कारगिल (2003): LOC कारगिल को जे.पी. दत्ता ने डायरेक्ट किया। इस वॉर फिल्म में 33 एक्टर्स थे। इसमें संजय दत्त, अजय देवगन, सैफ अली खान, अभिषेक बच्चन, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, मनोज बाजपेयी, नागार्जुन, रानी मुखर्जी, ईशा देओल, रवीना टंडन समेत कई बड़े एक्टर्स थे। इसे हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी मल्टीस्टारर फिल्मों में गिना जाता है।

ओम शांति ओम (2007): ओम शांति ओम को फराह खान ने डायरेक्ट किया। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की इस फिल्म के गाने 'दीवानगी–दीवानगी' में 30 से ज्यादा बॉलीवुड सेलेब्स ने कैमियो किया था।

स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता

फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया, फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में दागा विजयी गोल

स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। उसने न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में 2022 की चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। स्पेन के लिए फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल किया। स्पेन दूसरी बार फीफा वर्ल्ड चैंपियन बना है। उसने पहली बार 2010 में नीदरलैंड को हराकर यह ट्रॉफी जीती थी।

मार्टिनेज ने 105 मिनट तक अकेले लड़ाई लड़ी

अगर यह मुकाबला 105 मिनट तक बराबरी पर रहा तो इसकी सबसे बड़ी वजह अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज थे। स्पेन पूरे मैच में लगातार अटैक करता रहा। कभी लामिन यमाल ने बॉक्स के बाहर से शॉट लगाया, कभी ओयारजबाल ने मौका बनाया तो कभी पेड्री और निको विलियम्स गोल के करीब पहुंचे। हर बार मार्टिनेज ने खुद को गेंद और गोलपोस्ट के बीच खड़ा कर दिया।

लगभग अकेले लड़ रहे मार्टिनेज की दीवार आखिरकार 106ठे मिनट में ढह गई। निको विलियम्स का हेडर फेरन टोरेस तक पहुंचा, जिन्होंने बॉल गोलपोस्ट में डाल दिया। इस तरह स्पेन 1-0 से आगे हो गया।

मेरिनो चूके... टोरेस ने इतिहास लिख दिया

103वें मिनट में निको विलियम्स ने ऐसा क्रॉस डाला, जिसे देखकर स्पेनिश फैंस जश्न मनाने को तैयार हो गए थे। मिकेल मेरिनो को लगभग खाली गोल मिला, लेकिन उनका हेडर बाहर चला गया।

तीन मिनट बाद वही निको विलियम्स फिर बाएं फ्लैंक से पहुंचे। इस बार उन्होंने बैक पोस्ट पर हेडर से गेंद फेरन टोरेस के सामने गिराई। फेरन टोरेस ने बिना एक पल गंवाए दाएं पैर से ऐसा शॉट लगाया कि गेंद सीधे नेट में जा समाई।

यमाल ने मेसी की चमक फीकी कर दी

यह फाइनल एक तरह से दो पीढ़ियों का मुकाबला भी था। एक तरफ 39 साल के लियोनेल मेसी थे, दूसरी

ओर 20 साल के लामिन यमाल। मेसी से उम्मीद थी कि वे एक बार फिर बड़े मैच में कमाल कर दिखाएंगे, लेकिन स्पेन की मिडफील्ड और डिफेंस ने उन्हें कभी खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। दूसरी ओर यमाल लगातार अर्जेंटीना के डिफेंस पर हमला करते रहे। 2007 में एक फोटोशूट के दौरान 20 साल के लियोनेल मेसी ने 6 महीने के लामिन यमाल को गोद में उठाया था। अब यमाल ने मेसी को फाइनल में हरा दिया। 2007 में एक फोटोशूट के दौरान 20 साल के लियोनेल मेसी ने 6 महीने के लामिन यमाल को गोद में उठाया था। अब यमाल ने मेसी को फाइनल में हरा दिया।

एंजो का रेड कार्ड... और यहीं पलट गया फाइनल

अर्जेंटीना 90 मिनट तक किसी तरह मुकाबले में बनी रही। ऐसा लगा कि टीम मैच को पेनल्टी शूटआउट तक ले जाना चाहती थी, लेकिन इंजरी टाइम में एंजो फर्नांडिज ने ऐसी गलती कर दी, जिसने पूरी बाजी पलट दी। पाउ क्यूबार्सी पर टैकल के बाद रेफरी ने एंजो को दूसरा यलो कार्ड दिखाया। यह उनका मैच का दूसरा यलो कार्ड था। इस तरह उनके दो यलो कार्ड, रेड कार्ड में कन्वर्ट हो गए। उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा और अर्जेंटीना 10 खिलाड़ियों के साथ रह गई। इसके बाद स्पेन ने गेंद पर और ज्यादा कब्जा जमा लिया।

स्पेन की पहचान फिर बनी बॉल पजेशन

स्पेन की पहचान हमेशा से गेंद पर नियंत्रण रखने वाली टीम की रही है। इस फाइनल में भी वही अंदाज दिखा। रोड्री ने मिडफील्ड में पूरे मैच की रफ्तार तय की। अर्जेंटीना को काउंटर अटैक का मौका ही नहीं मिला। स्पेन ने करीब 65% समय गेंद अपने पास रखी।

आखिरी सीटी के बाद जश्न... और फिर लड़ाई

रेफरी की अंतिम सीटी बजते ही स्पेनिश खिलाड़ी मैदान पर दौड़ पड़े। कोई घुटनों के बल बैठ गया, कोई आसमान की ओर देखने लगा, तो कोई अपने साथी खिलाड़ियों से लिपट गया। 16 साल का इंतजार खत्म हो चुका था।

दूसरी ओर अर्जेंटीना के खिलाड़ियों की निराशा साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच नोकझोंक भी हुई, लेकिन मामला जल्द शांत हो गया। इसके बाद ट्रॉफी स्पेन के कप्तान के हाथों में पहुंची और पूरा स्टेडियम 'वीवा एस्पाना' (स्पेन जिंदाबाद) के नारों से गूंज उठा।

एम्बाप्पे ने जीता गोल्डन बूट, मेसी दूसरे नंबर पर

फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा गोल फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे ने किए। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 10 गोल और 4 असिस्ट के साथ गोल्डन बूट अपने नाम किया। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ दूसरे स्थान पर रहे।

ड्रॉ से शुरुआत, जीत के साथ खत्म हुआ स्पेन का सफर

स्पेन ने वर्ल्ड कप की शुरुआत केप वर्डे के खिलाफ ड्रॉ से की थी, लेकिन इसके बाद टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ग्रुप स्टेज में सऊदी अरब को 4-0 और उरुग्वे को 1-0 से हराकर नॉकआउट में जगह बनाई। इसके बाद स्पेन ने लगातार ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, बेल्जियम और फ्रांस जैसी मजबूत टीमों को हराया।

एम्बाप्पे के नाम सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप गोल

फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 ने सबसे बड़ा रिकॉर्ड गोल स्कोरिंग लिस्ट में देखा। फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे ने 10 गोल के साथ अपना कुल वर्ल्ड कप गोल आंकड़ा 22 तक पहुंचाया और जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजे (16) का रिकॉर्ड पीछे छोड़ते हुए इतिहास के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी भी 21 गोल के साथ क्लोजे से आगे निकलकर दूसरे स्थान पर पहुंच गए।

‘नीली क्रांति’ से समृद्धि की ओरः मछली पालन बना ग्रामीण विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया आधार

सरकारी योजनाओं से मिल रहा संबल, मत्स्य पालन से खुल रहे आय और स्वरोजगार के नए द्वार

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ सहायक व्यवसायों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इन्हीं में मछली पालन आज केवल भोजन का स्रोत नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार, आय और आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम बन गया है। कम लागत, कम समय में बेहतर उत्पादन और बाजार में बढ़ती मांग के कारण यह व्यवसाय गांवों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

मत्स्य पालन जैसे आयवर्धक व्यवसायों को अपनाएं

छत्तीसगढ़ में मछली पालन राज्य के प्रमुख और अत्यधिक लाभदायक व्यवसायों में से एक है। कृषि का दर्जा मिलने से इसे बढ़ावा मिला है और राज्य मत्स्य बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भी किसानों से आह्वान किया है कि वे खेती को केवल धान तक सीमित न रखें। दलहन, तिलहन, उद्यानिकी, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन जैसे आयवर्धक व्यवसायों को अपनाएं। इसी सोच के अनुरूप भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं, जिससे किसानों और ग्रामीण युवाओं को रोजगार-स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही नई मजबूती

ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन सीमित भूमि और कम पूंजी में शुरू किया जा सकता है। तालाब, जलाशय, नहर और अन्य जल स्रोतों का उपयोग कर किसान अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। बढ़ती आबादी और पौष्टिक भोजन की मांग से मछली की खपत लगातार बढ़ रही है। प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर मछली स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है।

मत्स्य पालन में रोजगार के बड़े अवसर

मत्स्य पालन न सिर्फ किसानों की आय बढ़ाता है, बल्कि मत्स्य बीज उत्पादन, आहार निर्माण, परिवहन, प्रसंस्करण और विपणन जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार के बड़े अवसर देता है।

राज्य पोषित योजनाओं से बढ़ रही संभावनाएं, शिक्षण एवं प्रशिक्षण

छत्तीसगढ़ सरकार मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता दे रही है। आधुनिक तकनीकों के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण में तालाब प्रबंधन, मत्स्य बीज उत्पादन, रोग नियंत्रण और विपणन की जानकारी दी जाती है। तकनीकी उन्नयन के लिए विशेष प्रशिक्षण भी होते हैं।

मत्स्य पालकों को राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण

प्रगतिशील मत्स्य पालकों को राज्य के बाहर सफल मॉडल देखने भेजा जाता है, ताकि वे नई तकनीक

अपनाने के लिए प्रेरित हों।

सहकारी समितियों को अनुदानः उत्पादन और विपणन व्यवस्था मजबूत करने के लिए मत्स्य सहकारी समितियों को आर्थिक मदद दी जाती है।

नाव-जाल सहायताः अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को नाव-जाल देकर पारंपरिक मछली पकड़ने को बढ़ावा दिया जा रहा है।

फुटकर विक्रेताओं को मददः आइस बॉक्स, तराजू जैसे उपकरण देकर छोटे मछुआरों को बेहतर बाजार और लाभ दिलाया जा रहा है।

स्पॉन संवर्धन व झींगा पालनः अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग को स्पॉन संवर्धन और झींगा सह मछली पालन के लिए विशेष सहायता मिल रही है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना दे रही नई उड़ान

केंद्र-राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से चल रही इस योजना का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन बढ़ाना, रोजगार सृजन और मछुआरों की आय बढ़ाना है।

आधुनिक तकनीक को प्रोत्साहनः मत्स्य बीज उत्पादन बढ़ाने और नए तालाब निर्माण के लिए आकर्षक अनुदान दिया जा रहा है। बेहतर वृद्धि के लिए संतुलित आहार, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS) जैसी वैज्ञानिक पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सजावटी मछली व केज कल्चरः मत्स्य पालन के क्षेत्र में सजावटी मछली पालन इकाइयों और जलाशयों में केज कल्चर से स्वरोजगार के नए अवसर बन रहे हैं।

विपणन को मजबूतीः मत्स्य पालकों को शीत संयंत्र, प्रशीतित वाहन, आइस बॉक्स युक्त मोटरसाइकिल, ई-रिक्शा और लाइव फिश सेंटर से मछलियों की गुणवत्ता बनाए रखकर बेहतर विपणन सुनिश्चित हो रहा है।

मछुआरों के लिए सामाजिक सुरक्षा का कवच

बचत सह राहत योजनाः मछली पकड़ने की बंद (15 जून से 15 अगस्त तक) अवधि में आर्थिक मदद के लिए केंद्र-राज्य के सहयोग से यह योजना चल रही है।

निःशुल्क समूह बीमा योजनाः मत्स्य पालकों के दुर्घटना, मृत्यु या अपंगता की स्थिति में मछुआरों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा मिलती है।

आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर कदम

मछली पालन आज ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक आत्मनिर्भरता का अहम माध्यम बन गया है। सरकार की योजनाएं किसानों, युवाओं, महिलाओं और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग को स्वरोजगार के नए अवसर दे रही हैं। आधुनिक तकनीक, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण से मत्स्य क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं बन रही हैं।

मत्स्य पालन आत्मनिर्भर और समृद्ध ग्रामीण भारत के निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम

इच्छुक हितग्राही अपने नजदीकी मत्स्य विभाग कार्यालय से संपर्क कर योजनाओं की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। मछली पालन न सिर्फ आय बढ़ाने का जरिया है, बल्कि आत्मनिर्भर और समृद्ध ग्रामीण भारत के निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम भी है।

धनंजय राठौर,
संयुक्त संचालक जनसंपर्क, रायपुर

विष्णु का सुशासनः सेवा सेतु से सशक्त जनसेवा

छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार और विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकार ने आम लोगो के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने उनके जीवन स्तर को बेहतर करने और सरकारी कामकाज में तेजी लाने अनेको प्रयास किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आम लोगो को दैनिक जीवन में सरकारी काम को लेकर होने वाली परेशानियों के निराकरण करने योजना बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को आत्मसात करते हुए छत्तीसगढ़ के सवा करोड़ लोगो को घर बैठे काम करने 'सेवा सेतु' बनाया। जिसमे छत्तीसगढ़ का प्रत्येक रहवासी अपने मुलभुत जरुरी सरकारी कामो को अपने मोबाइल और कंप्यूटर के माधयम से घर में बैठकर ही पूरा कर सकते है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 29 अप्रैल 2026 को सेवा सेतु (Seva Setu) पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से बेहद जरुरी 441 सरकारी सेवाओं हो सकता है।

प्रदेश के लोगों की समस्याओं का हल निकालने के लिए प्रभावी तरीकों का प्रयोग किया जा रहा हैं, असल में 'सेवा सेतु ' 'सुशासन तिहार' और 'जनदर्शन' जैसे आयोजनों को लोगों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए ही बनाया गया है सरकार के मंशानुसार अधिकारियों की उपस्थिति में उनकी समस्याओं का निपटारा किया जा रहा हैं, दर्जनो विभाग जैसे जल बोर्ड, शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, रायपुर नगर निगम आदि के अधिकारीयों की उपस्तिथि मे लोगों की समस्याएं, शिकायतें, सुझाव और ज़रूरतें सीधे मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखी जा रही हैं हैं । मुख्यमत्री ने संबद्ध अधिकारियों से उनको हल करने का आदेश जारी किया हुआ हैं, अधिकतर शिकायतों में अपराध, पेयजल, दाखिला, स्वास्थ्य, सडक़, अतिक्रमण आदि से जुड़ी हुई हैं और पेंशन, राशन कार्ड, और आवास जैसी मूलभूत समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा हैं।

सेवा सेतु का शुभारंभ-

मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश में सुशासन की परिकल्पना के साथ सेवा सेतु की शुरुआत की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन का अर्थ है- जनता का समय बचे, सुविधा बढ़े और हर सेवा सहजता से मिले। इसी सोच के साथ सेवा सेतु पोर्टल पर जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन सहित 36 विभागों की 520 सेवाएं अब घर बैठे ऑनलाइन उपलब्ध हैं। सरल प्रक्रिया, पारदर्शी व्यवस्था और डिजिटल सुशासन - यही हमारी प्रतिबद्धता है।साल 2003 में प्रारंभ हुए चॉइस (CHOICE) सेण्टर मॉडल से लेकर वर्ष 2015 के ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से आम लोगो के जाति-निवास प्रमाण पत्र बनाने का काम होता था। इसे मुख्यमत्री

विष्णुदेव साय ने आधुनिक तकनीक से अपग्रेड करते हुए सेवा सेतु से रूप में शुभारम्भ किया। जिसमे अब घर बैठे ही लोगो 441 प्रकार के सरकारी काम कर सकते है, जिसमे आय, जाति, निवास, राशन कार्ड और विवाह पंजीयन जैसे प्रमुख काम घर बैठे हो सकेगा। इस परियोजना का संचालन राज्य स्तर पर चिप्स (CHiPS) द्वारा किया जा रहा है, जबकि जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेंस सोसाइटी (DeGS) के माध्यम से इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। नई प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), आधार, व्हाट्सएप और 'भाषिणी' जैसी उन्नत तकनीकों का एकीकृत उपयोग किया गया है, जिससे नागरिक व्हाट्सएप के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे, सेवा की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और डिजिटल प्रमाण-पत्र भी प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही आधार आधारित ई-केवाईसी, डिजी लॉकर, ई-प्रमाण और उमंग जैसे प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण कर सेवाओं को और अधिक सरल, सुरक्षित और सुलभ बनाया गया है।

'सेवा सेतु' में ट्रेजरी और ई-चालान का एकीकरण किया गया है, जिससे नागरिक एक ही प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन भुगतान कर तत्काल डिजिटल रसीद प्राप्त कर सकेंगे तथा डीबीटी के माध्यम से योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी, जिसकी रीयल-टाइम ट्रैकिंग एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से संभव होगी। पोर्टल में क्यूआर कोड आधारित प्रमाण-पत्र सत्यापन, क्लाउड स्टोरेज, डिजिटल सिग्नेचर, रीयल-टाइम डैशबोर्ड और एमआईएस रिपोर्टिंग जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं तथा यह पोर्टल 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे भाषा की बाधा समाप्त हो गई है।

सुविधाओं का विस्तार-

सेवा सेतु प्रदेश के 800 से अधिक लोक सेवा केंद्र, 1000 से अधिक चॉइस सेंटर और 15,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर सक्रिय हैं, जहां से प्रत्येक व्यक्ति अपना सरकारी काम कर सकता है। 'सेवा सेतु' में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जनसेवा के केंद्र में रखते हुए आवेदन प्रक्रिया को सरल और तकनीकी रूप से बाधारहित बनाया गया है, जिससे शासन और नागरिकों के बीच की दूरी तेजी से कम हो रही है और सेवाएं सीधे नागरिकों के हाथों तक पहुंच रही हैं। व्हाट्सएप इंटरफेस के माध्यम से नागरिक विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे, पावती रसीद और दस्तावेजों के लिंक तुरंत प्राप्त कर सकेंगे तथा अनुमोदन के पश्चात डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र सीधे व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकेंगे। वर्तमान में यह सुविधा 25 सेवाओं के लिए उपलब्ध है, जिसे शीघ्र ही सभी सेवाओं तक विस्तारित किया जाएगा। प्रत्येक प्रमाण-पत्र में क्यूआर कोड आधारित सत्यापन की सुविधा दी गई है, जबकि कैप्चा, ओटीपी और ईमेल आधारित प्रमाणीकरण जैसी व्यवस्थाएं सुरक्षा को सुदृढ़ करती हैं। नागरिकों की पहचान को विश्वसनीय बनाने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी की सुविधा प्रारंभ की गई है तथा सुरक्षित लॉगिन हेतु डिजिलॉकर और ई-प्रमाण जैसी प्रणालियों को एकीकृत किया गया है।

पर्यटकों को लेकर जा रही नाव पलटी, 15 की मौत

वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास शनिवार को भारतीय पर्यटकों को लेकर जा रही एक नाव समुद्र में पलट गई. इस दर्दनाक हादसे में 15 भारतीयों की मौत हो गई, जबकि 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया. घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन का राहत बचाव अभियान शुरू हो गया. फिलहाल भारतीय दूतावास पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है. प्रभावित परिवारों की मदद के लिए हो ची मिन्ह सिटी और हनोई में इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर भी बनाए गए हैं।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि नाव में कुल 36 लोग सवार थे. इनमें 32 भारतीय पर्यटक, 3 क्रू मेंबर और 1 अटेंडेंट शामिल थे. हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की जान चली गई, जबकि बाकी 21 लोगों को बचा लिया गया

हादसे की खबर मिलते ही वियतनाम में मौजूद भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करके इस बात की पुष्टि की. दूतावास ने अपने ट्वीट में लिखा, 'एक बेहद दुखद घटना में, कुछ घंटे पहले वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास कई भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक नाव पलट गई है. हादसे के सटीक विवरण का पता लगाया जा रहा है, स्थानीय अधिकारियों की तरफ से खोज और बचाव अभियान फिलहाल जारी है. '

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, नाव होन मे रुट द्वीप से एन थोई पोर्ट लौट रही थी. इसी दौरान तट से करीब 400 मीटर दूर समुद्र में नाव पलट गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, उस समय समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही थीं, जिससे हादसा हुआ. हालांकि, घटना के सही कारणों की जांच अभी जारी है. बता दें कि फू क्वोक वियतनाम का सबसे बड़ा द्वीप है और पिछले कुछ वर्षों में यह भारतीय पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है. यही वजह है कि बड़ी संख्या में भारतीय यहां छुट्टियां मनाने पहुंचते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम में भारतीय पर्यटकों के साथ हुए नाव हादसे पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने इस घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द ठीक होने की उम्मीद जताई। इस बीच आंध्र प्रदेश सरकार भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है. सरकार ने कहा है कि यह जानकारी जुटाई जा रही है कि नाव हादसे में आंध्र प्रदेश के कितने लोग प्रभावित हुए हैं. फिलहाल राज्य के कितने लोगों की मौत हुई है, इसकी सटीक पुष्टि नहीं हुई है।

फिलहाल भारतीय दूतावास ने कहा है कि वह स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक घटना के समय समुद्र में ऊंची लहरें थीं, हालांकि नाव पलटने की असली वजह का पता लगाने के लिए पड़ताल जारी है।

जतमई-घटारानी वाटरफॉल

छत्तीसगढ़ अपनी अनुपम प्राकृतिक सुंदरता और घने जंगलों के लिए जाना जाता है, जहां उत्तर से लेकर दक्षिण छत्तीसगढ़ तक अनगिनत मनमोहक जलप्रपात मौजूद हैं. मानसून के आगमन के साथ ही इन झरनों की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है, और इन दिनों ये स्थल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं.इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मध्य छत्तीसगढ़ के एक ऐसे ही खूबसूरत और प्रसिद्ध जलप्रपात की, जो राजधानी रायपुर के पड़ोसी जिले गरियाबंद में स्थित है जतमई-घटारानी।

गरियाबंद जिले के जतमई–घटारानी के घने जंगलों के बीच स्थित यह जलप्रपात पर्यटकों के लिए एक अद्भुत और रोमांचक अनुभव प्रदान करता है. रायपुर राजधानी से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह रमणीय स्थल, मानसून की झमाझम बारिश के बाद अपने पूरे शबाब पर है. नदी–नाले और झरने अब पूरे वेग से बह रहे हैं, जिससे यहां का प्राकृतिक सौंदर्य और भी अधिक निखर गया है.

मुख्य जतमई वाटरफॉल जंगल के बीचों–बीच लगभग 40 फीट की ऊंचाई से पत्थरों पर टकराते हुए नीचे गिरता है. पहाड़ से नीचे उतरती, उछलती–कूदती और बूंदों को बिखेरती जलधारा धीरे–धीरे चौड़ी होती जाती है और फिर गरजते हुए तीव्र वेग से नीचे गिरती है.झरना जतमई माता मंदिर और शिव मंदिर के ठीक बीच से होकर गुजरता है, जिससे यहां का परिवेश एक आध्यात्मिक और प्राकृतिक संगम का अद्भुत नजारा पेश करता है.

40 फीट की ऊंचाई से गिरता पानी ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी सफेद चादर ने चट्टानों को ढक लिया हो. झरने से उड़ती पानी की बारीक बूंदें, आसपास पसरा हल्का कोहरा और ठंडी हवा का झोंका यहां आने वाले हर व्यक्ति को एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है. झरने की गर्जना और प्रकृति की शांत गोद का मिश्रण यहां पर्यटकों को मुग्ध कर देता है.

सुप्रसिद्ध जतमई–घटारानी का यह पर्यटन स्थल, खासकर मानसून के दौरान, बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींचता है. परिवार और दोस्तों के साथ यहां आकर लोग प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाते हैं, पिकनिक मनाते हैं और झरने के शीतल जल में खड़े होकर तरोताजा महसूस करते हैं।

– निवेदन –

स्वतंत्र बोल से संबंधित कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो आप नीचे लिखे पते पर भेज सकते हैं। फोन और ई-मेल पर भी जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा आपके क्षेत्र से घटित कोई घटना, समाचार, या अन्य कोई गतिविधि जो पत्रिका में प्रकाशन योग्य हो.. तो उसे भी भेज सकते हैं।

छत्तीसगढ़ का सबसे विश्वसनीय हिन्दी मासिक पत्रिका तेजी से बढ़ता यूट्यूब चैनल और न्यूज वेबसाइट को निर्भीक और जनपक्षीय पत्रकारिता के लिये आर्थिक रूप से सहयोग करें।

बंधन बैंक

बैंक खाता नंबर – 20100031810292

आईएफएससी कोड – BDBL0001958

SB स्वतंत्र बोल

संपादक स्वतंत्र बोल

डी-317 बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने टैगोर नगर, रायपुर (छ.ग.)

97543-74333, bolswatantra@gmail.com

swatantrabol swatantrabol www.swatantrabol.com हिन्दी मासिक पत्रिका

सेवा सेतु
जनता के द्वार, डिजिटल सरकार

डिजिटल सुशासन की नई पहचान
सेवाएं हुईं **त्वरित, पारदर्शी और आसान**

520
शासकीय सेवाएं

घर बैठे, एक क्लिक में

नागरिकों के लिए सरल, तेज और पारदर्शी सेवाएं

95.9%
आवेदनों का निराकरण

- **38 लाख+** आवेदन
- **16,700+** सेवा केंद्र
- **36 विभाग** एक मंच पर

प्रमुख सेवाएं

- ✓ **जाति प्रमाण** पत्र
- ✓ **आय प्रमाण** पत्र
- ✓ **निवास प्रमाण** पत्र
- ✓ **विवाह प्रमाण** पत्र
- ✓ **राशन कार्ड** सेवाएं
- ✓ **पेंशन** योजनाएं
- ✓ नाम **परिवर्तन सेवा**
- ✓ व्यापार **लाइसेंस**

अधिक जानकारी हेतु
◂ स्कैन करें

जनहित में तकनीक, जनसेवा में नवाचार

sewasetu.cgstate.gov.in

92034 06400

RO. No. 13902/7